

रिपोर्ट की थीम

इतिहास में महामारियों के देखे गए पैटर्न के साथ-साथ महामारी विज्ञान की अंतर्दृष्टि हमें बताती है कि जब तक वे स्थानिक नहीं हो जाते, तब तक सीमित प्रभाव के छिटपुट फैलाव के साथ उनकी तेजी से समाप्ति की संभावना होती है। कोविड-19 महामारी इतिहास में दर्ज हो जाएगी क्योंकि यह दुनिया के अब तक के सबसे खराब स्वास्थ्य संकटों में से एक है। इसका आर्थिक प्रभाव कई और वर्षों तक बना रह सकता है और हमें आजीविका के पुनर्निर्माण, व्यवसायों की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है।

भारत को उत्पादन, जीवन और आजीविका के क्षेत्र में महामारीजनित नुकसान हुआ जिसे ठीक होने में वर्षों लग सकते हैं। आर्थिक गतिविधि दो साल बाद भी मुश्किल से प्री-कोविड स्तर तक पहुंच पाई है। भारत की आर्थिक बहाली को गहरी संरचनात्मक बाधाओं के साथ-साथ महामारी के दुष्प्रभावों से भी कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। रूस-यूक्रेन संघर्ष ने भी सुधार की गति को कम कर दिया है, इसके प्रभाव कमोडिटी की उच्च कीमतों, कमजोर वैश्विक संवृद्धि दृष्टिकोण और कठिन वैश्विक वित्तीय स्थितियों के रूप में प्रकट हुए हैं। भविष्य के व्यापार, पूंजी प्रवाह और आपूर्ति शृंखला को प्रभावित करने वाले, वैश्विक अलगाव के बारे में चिंताओं ने कारोबारी माहौल की अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया है। इस पृष्ठभूमि में, भारत का मध्यावधिक संवृद्धि दृष्टिकोण, संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने और नई संवृद्धि के अवसरों का दोहन करने हेतु नीतिगत उपायों पर निर्भर है। मुद्रा और वित्त संबंधी इस वर्ष की रिपोर्ट की थीम (मूल विषय) “पुनरुत्थान और पुनर्निर्माण” है।

2016-17 की दूसरी छमाही से ही अर्थिक गतिविधि में कमी और उसके संरचनात्मक और चक्रीय चालकों की पृष्ठभूमि में यह रिपोर्ट कोविड जनित आर्थिक गिरावट की पड़ताल करता है। टीकाकरण में प्रगति सहित अभूतपूर्व लोक कल्याणकारी

नीतिगत सहयोग एक प्रमुख धुरी रहा है। लोक कल्याणकारी नीति कार्रवाई के बल पर अब संवृद्धि उत्तरोत्तर पुनर्जीवित हो रही है - यहां तक कि राजकोषीय नीति के रुख का लक्ष्य, पूंजीगत व्यय चक्र को पुनर्जीवित करना है और मौद्रिक नीति, समायोजनकारी नीति की वापसी पर ध्यान केंद्रित करते हुए समायोजनकारी बनी हुई है ताकि यह सुनिश्चित की जा सके कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर रहते हुए संवृद्धि में सहयोगी बनी रहे। पिछले संकटों के सबक उत्पादन के स्थायी नुकसान की वास्तविकता को प्रकट करते हैं, जो निवेश के गहरे घावों और संबंधित पूर्व-संकट प्रवृत्तियों^ए के सापेक्ष पूंजी और कुल फैक्टर उत्पादकता (टीएफपी) में कमी में परिलक्षित होता है। दिवालियापन के रूप में महामारी के संभावित हिस्टेरिसीस प्रभाव और क्षमता विनाश अब तक पूरी तरह से निर्धारित नहीं किए गए हैं और तुलन पत्र की हानि और नई निवेश मांग में कमी के माध्यम से खुद को प्रकट कर सकते हैं।

कॉरपोरेट तुलन पत्र ने लीवरेज करके और अर्थसुलभ आस्तियों को बढ़ाकर महामारी का मुकाबला किया है, लेकिन निवेश वहनीयता, जो कि नए सिरों से कैपेक्स चक्र को चालित करेगा, अभी भी कमजोर है। कमजोर घरेलू तुलन पत्र और संपर्क-गहन गतिविधि से विस्थापित श्रमिकों ने उपभोग की मांग और पूंजी की गुणवत्ता को प्रभावित किया है। नतीजन, भारत का प्रवृत्ति संवृद्धि पथ नीचे की ओर स्थानांतरित हो सकता है जो संवृद्धि को मजबूत करने के लिए उपायों की एक व्यापक श्रेणी को लागू करने में तात्कालिकता की मांग करता है, जहाँ निवल-शून्य संक्रमण लागत, अवैश्वीकरण और बाधित आपूर्ति शृंखलाओं को समायोजित किया गया है।

शेष रिपोर्ट छह अध्यायों में गठित है। अध्याय 1 शीर्षक “महामारी से नुकसान” महामारी के अनुभव से सबक लेता है। इसमें भारत में संवृद्धि पर कोविड के प्रभाव का आकलन शामिल है, जो

^ए Cerra, M.V. and Saxena, M.S.C. (2017), “Booms, Crises, and Recoveries: A New Paradigm of the Business Cycle and its Policy Implications”, आईएमएफ वर्किंग पेपर, No. 17/250, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।
आईएमएफ (2018), “Challenges to Steady Growth”, World Economic Outlook, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अक्टूबर।

सुदृढ़ता दिखाने वाले क्षेत्रों को अलग करता है। यह पुनरुत्थान के जोखिमों की पड़ताल करता है और उन वर्षों की संख्या का आकलन प्रस्तुत करता है जो भारत को एक काल्पनिक कोविड-रहित प्रवृत्ति जीडीपी को प्राप्त करने में लग सकता है।

अध्याय II आर्थिक सुधार की इंजीनियरिंग में महामारी-रोधी मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों की भूमिका प्रस्तुत करता है। यह, रिपोर्ट के विषय के अनुरूप, भारत में वर्तमान मौद्रिक और राजकोषीय विन्यास को एक दूरदेशी दृष्टिकोण से भी जांचता है। यह अध्याय, संकट में राजकोषीय प्रोत्साहन की भूमिका और संवृद्धि के लिए सामान्य समय में राजकोषीय सुदृढ़ता के महत्व का भी अध्ययन करता है। श्रेयोल्ड स्तर से ऊपर बनी हुई मुद्रास्फीति से संवृद्धि के जोखिमों को देखते हुए, एक अनुभवजन्य अन्वेषण मुद्रास्फीति पर चलनिधि के प्रारंभिक प्रभावों के साथ-साथ सार्वजनिक ऋण के लिए सीमाओं की पहचान करता है। यह अध्याय, ऋण के अनुमानित सीमा स्तर के सापेक्ष, अगले पांच वर्षों में भारत में संभावित ऋण समेकन पथ की पहचान करने के लिए, ऋण धारणियता के प्रमुख मापदंडों - संवृद्धि, मुद्रास्फीति, ब्याज दर और प्राथमिक शेष - के लिए व्यवहार्य वैकल्पिक मार्ग प्रस्तुत करता है।

अध्याय III शीर्षक "वृद्धि को पुनर्जीवित करने हेतु संरचनात्मक मुद्दे" भारत की पूर्व-महामारी प्रवृत्ति वृद्धि को पुनर्जीवित करने और महामारी के बाद इसे ऊपर उठाने में संरचनात्मक नीतियों की भूमिका की पड़ताल करता है। यह संवृद्धि में संरचनात्मक बाधाओं की जांच करता है, जो एक अर्थ में, पूर्व-महामारी विरासत हैं- कम पूंजी निर्माण के रूप में कृषि क्षेत्र में असंतुलन, अनुसंधान एवं विकास व्यय में गिरावट, कम फसल की पैदावार, फसल विविधता और तीव्रता की कमी, और अत्यधिक निर्भरता सब्सिडी और मूल्य समर्थन योजनाओं पर; प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद खनन में अपर्याप्त निवेश; योजित सकल मूल्य (जीवीए) में विनिर्माण के हिस्से का लगभग ठहराव; सुस्त उत्पादकता; शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान एवं विकास

पर अपर्याप्त व्यय; और व्यापार करने की उच्च लागत। ये जोखिम जनसांख्यिकीय संक्रमण के कारण बढ़ जाते हैं जिसमें प्रजनन दर प्रतिस्थापन दर से नीचे आ जाती है, और श्रम बल की भागीदारी में गिरावट आती है। इस अध्याय में कारक और उत्पाद दोनों बाजारों को कवर करते हुए, रणनीतिक सुधारों की एक विस्तृत शृंखला के माध्यम से निजी निवेश में निरंतर गिरावट को दूर करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।

अध्याय IV एक रणनीतिक नीतिगत रीसेट के माध्यम से भारत के संभावित उत्पादन को आगे बढ़ाने में निर्यात और विदेशी पूंजी की भूमिका पर प्रकाश डालता है जो भारत को एक अधिक खुली अर्थव्यवस्था में बदल देता है। यह नवाचारों और अनुसंधान और विकास, महत्वपूर्ण इनपुट - घरेलू और आयातित दोनों - तक आसान पहुंच और व्यापार पूरकता के आधार पर अधिक प्रभावी व्यापार-सृजनात्मक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर अधिक जोर देता है। यह निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए सीमांत प्रौद्योगिकियों को अपनाने के अवसरों की पड़ताल करता है और विदेशी पूंजी को उत्पादक रूप से अवशोषित करने के लिए अर्थव्यवस्था की क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है।

अध्याय V भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त के धीमे प्रवेश और उसके समाधान की चर्चा करता है। इसमें हरित अर्थव्यवस्था और डिजिटल दुनिया में संक्रमण का प्रबंधन करते हुए अर्थव्यवस्था में ऋण प्रवाह को पुनः सक्रिय करने में वित्तीय क्षेत्र के सुधारों की भूमिका की चर्चा की गई है। संक्षेप में, यह अध्याय प्रश्न पूछता है: क्या वित्त, एक महामारी के बाद की पुनरुत्थान में संवृद्धि का, नेतृत्व कर सकता है? विशेष रूप से, यह अध्याय संवृद्धि को मजबूत करने में डिजिटल और हरित वित्त की भूमिका और महत्व का आकलन करता है।

अंतिम अध्याय, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के लिए विशिष्ट सिफारिशों के साथ, पिछले पांच अध्यायों के निष्कर्षों का सार और संवृद्धि को फिर से जीवंत बनाने के लिए एक रोडमैप प्रस्तुत करता है।